डिजीटल पत्र

दैनिक

कांग्रेस दर्पण

पटना, 24 जुलाई, बुधवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना - 10

केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया, इस पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है।

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे अअ (अडानी अंबानी) को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है।

यह 'नकलची' और 'मोदी सरकार बचाओ' बजट हैः खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि 'मोदी सरकार बचाओ' बजट पेश किया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह 'नकलची बजट' है जिसमें सरकार कांग्रेस के 'न्याय' के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का ₹नकलची बजट₹ ! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी ₹रेवड़ियां₹ बांट रहा है, ताकि राजग बची रहे। यह ₹देश की तरक्की₹ का बजट नहीं, ₹मोदी सरकार बचाओ₹ बजट है।''

उन्होंने कहा, ''10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं, जो सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुना करना, सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन (आय) को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गांव-गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने लागू की थी। उन्होंने दावा किया महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वे श्रम बल में अधिक से अधिक शामिल हों।

ये बजट बहुत ही निराशाजनक

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

बिहार के लिये आवंटित बजट सिर्फ़ एक छलावा है। केंद्र सरकार ने शुरूआत से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। राज्य में नीतीश सरकार को बचाने के लिए ये घोषणा की गई है, इस बजट से बिहार को कुछ नहीं मिलने वाला॥

डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह

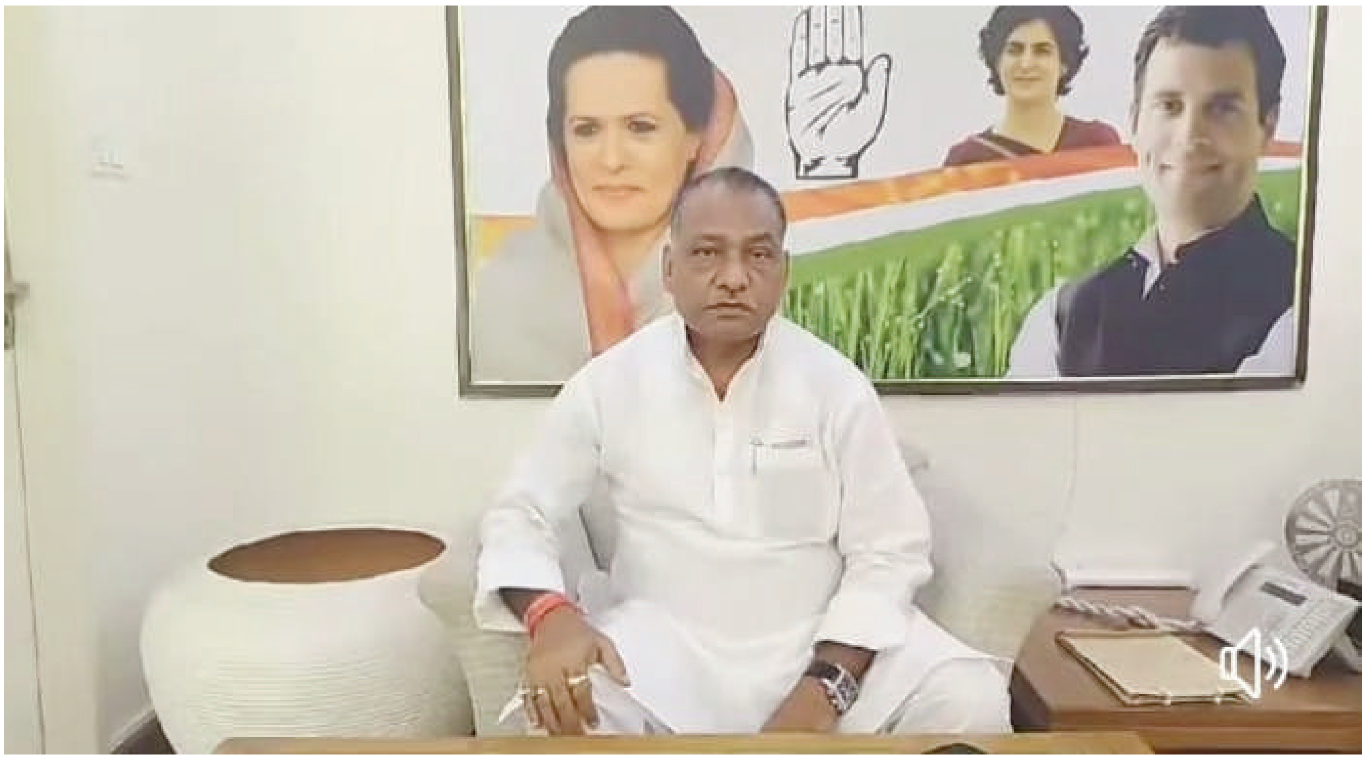

खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का पढ़ा घोषणा पत्र- पी चिदंबरम

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

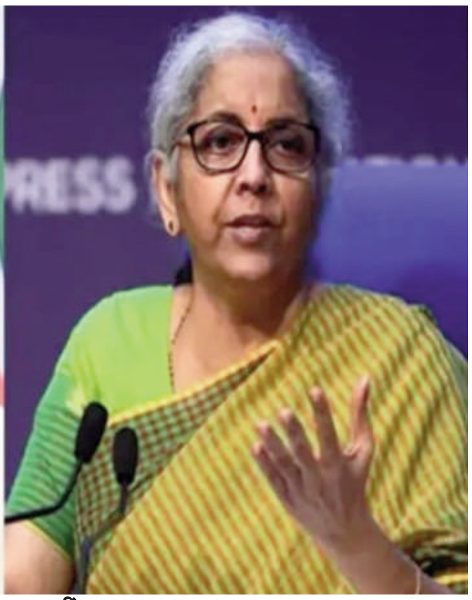

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते समय कई योजनाओं की शुरुआत की।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ा है। पूर्व वित्त मंत्री ने पर लिखा, ₹मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का घोषणापत्र 2024 पढ़ा।₹

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (एछक) को अपना लिया है, जो कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज नंबर 30 पर है।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ₹मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज 11 से प्रत्येक ट्रेनी को भत्ते के साथ ट्रेनिंग योजना शुरू की है।₹

उन्होंने वित्त मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि काश निर्मला सीतारमण कांग्रेस के घोषणापत्र से कुछ और विचार कॉपी कर पातीं।

पूर्व वित्त मंत्री ने पर लिखा, ₹मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने Angel Tax को खत्म कर दिया है। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रही थी और घोषणापत्र में पेज 31 पर भी ऐसा ही कहा गया है।₹

हालांकि, उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस पर आगे बात करेंगे।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नौ प्राथमिकताओं को सामने रखा, जिसमें रोजगार, कौशल, कृषि और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना सातवां बजट पेश करते हुए कहा, ₹इस बजट में हम रोजगार, कौशल, टरटए और मध्यम वर्ग पर फोकस करेंगे। उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बदला जाएगा।₹

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है।

आमंत्रण

दिनांकः 24 जुलाई 2024 (बुधवार)

समयः पूर्वा 11:30

स्थानः राधे कृष्ण बैंकेट हाल, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बोरिंग कनाल रोड, पटना से।

बेलगाम अपराध, विशेष राज्य पर बोले जा रहे लगातार झूठ, अग्निवीर, बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, एवं पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों के विरोध में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के तत्वाधान में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम दिनांक 24 जुलाई 2024 को पूर्वा 11:30 बजे से, राधे कृष्ण बैंकेट हाल, पंचमुखी हनुमान मंदिर बोरिंग कनाल रोड से करना सुनिश्चित किया गया है।

इस कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीनिवास बीवी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के आदरणीय अध्यक्ष डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह जी एवं बिहार विधानमंडल के नेता आदरणीय शकील अहमद खान साहब सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्यक्रम में आप अपने साथियों व समर्थकों के साथ सादर आमंत्रित हैं।

साभार

शिव प्रकाश गरीब दास

अध्यक्ष

बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस

कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एलान

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

बेंगलुरु। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने को कैबिनेट बैठक कर कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में उन्होंने ठएएळ सहित तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तीनों प्रस्ताव राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (ठएएळ), 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ हैं।

परिसीमन के खिलाफ प्रस्तावों को मंजूरी दी। सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों को विधानमंडल के चालू सत्र के दौरान आज पेश किए जाने की संभावना है।

बताया जाता है कि कैबिनेट ने 'ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024' को भी मंजूरी दे दी है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पुनर्गठन के लिए पूर्व मुख्य सचिव बीएस पाटिल के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय समिति ने इस महीने की शुरुआत में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

कहा जाता है कि मसौदा विधेयक में, समिति ने शहर पर शासन करने के लिए योजना और वित्तीय शक्तियों के साथ एक ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, और यह कई निगमों का भी प्रावधान करता है और 400 वार्डों तक का प्रावधान करता है।

नीट पर चल रहे विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने हाल ही में केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था।

युवा कांग्रेस ने की बैठक, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का करेंगे सहयोग

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

पाकुड़ : जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष तस्लीम आरिफ उर्फ बुलेट की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें पाकुड़ युवा कांग्रेस के जिला, विधान सभा और प्रखण्ड कमिटी के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.

झारखण्ड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन्डिया गठबंधन प्रत्याशी को विजय दिलाने की दिशा में कई बिन्दुओं पर चर्चा की गई. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) मोहम्मद खुर्शीद खान ने

कहा कि युवा कांग्रेस कमिटी के संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु यह बैठक आहूत की गई है. बैठक में कांग्रेस युवा कमिटी के जिलाध्यक्ष तस्लीम आरिफ उर्फ बुलेट, उपाध्यक्ष बेलाल शेख, मो नसीम आलम, जलालुद्दीन शेख, असगर अली, मिलन मंडल, गणेश शाह, बड़का टुडू, रॉबिन मंडल, बेणेश्वर मुर्मू सहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे.

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। बजट पेश होते ही कांग्रेस ने चुटकी ली। कहा कि खुशी है कि वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का 2024 का घोषणापत्र पढ़ा है। वहीं, सबसे पुरानी पार्टी ने यह भी कहा कि बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है। दरअसल, वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ पांच हजार रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है, जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को 'पहली नौकरी पक्की' नाम भी दिया था। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, 'मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणापत्र पढ़ा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 30 पर उल्लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) को अपना लिया है।

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणापत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लिखित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ-साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरू की है। काश, वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणापत्र में कुछ अन्य विचारों की नकल की होती। मैं शीघ्र ही छूटे हुए बिंदुओं की सूची बनाऊंगा। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, 'वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र-2024 से सीख ली है, जिसमें इसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था। हालांकि, अपनी चिरपरिचित शैली में योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य (एक करोड़ इंटर्नशिप) के साथ, सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्होंने दावा किया 10 साल के इनकार के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अंततः चुपचाप स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। रमेश ने कहा कि अब तक बहुत देर हो चुकी है और लगता है कि बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है।

ये बजट बहुत ही निराशाजनक

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था। ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था।

पूरा बजट दो प्रदेशों और दो विशेष राजनीतिक दलों को तवज्जो देने के लिए था, क्योंकि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं था।

लेकिन इसमें उन उद्योगपतियों के लिए बहुत कुछ था, जो BJP को चंदा देते हैं।

हम पिछले कई वर्षों से जो देखते आए हैं, वही इस बजट में भी देखने को मिलेगा।

ढट मोदी इस बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों की मदद करेंगे और उन सभी को नई जगह निवेश करने की सुविधाएं देंगे।

नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों की कंपनियों को बैंक और टैक्स नियमों से कैसे राहत मिले, यही बताया जाएगा।

वहीं, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदारों और ईमानदार टैक्सपेयर्स को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।

: लोकसभा में उप नेता *Gaurav Gogoi* जी

बहुत ही निराशाजनक बजट है, जो नरेंद्र मोदी का सिंहासन बचाने के लिए पेश किया गया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

ये बहुत ही निराशाजनक बजट है, जो नरेंद्र मोदी का सिंहासन बचाने के लिए पेश किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए MSP की गारंटी या खाद में सब्सिडी जैसा कुछ नहीं है।

वहीं रेलवे में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेलवे सुरक्षा, रेलवे भर्ती जैसी जरूरी चीजों की बात नहीं की गई। मोदी सरकार ने रेलवे का बजट बहुत कमजोर बनाया है।

देश के कई राज्यों में बाढ़ का माहौल है। लेकिन इस बजट में बाढ़ से राहत के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए।

मोदी सरकार के बजट में SC—ST का नाम ही नहीं है। इस बार SC—ST को जिस स्पेशल कंपोनेंट के तहत पैसा देना था, वो नहीं किया गया।

शायद मोदी सरकार, किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों से नाराज है, क्योंकि इन सभी ने INDIA गठबंधन का समर्थ किया है। इसलिए वे इनको नजरअंदाज कर सबक सिखाना चाहते हैं।

वहीं जातिगत जनगणना करने के लिए जितना बजट रखना था, उसका भी कोई जिक्रनहीं किया गया।

मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कांग्रेस की योजना कॉपी-पेस्ट की और नाम बदल दिया।

सारा देश महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन बजट में महंगाई के खिलाफ कदम उठाने की बात नहीं की गई।

इस बजट में सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए कुछ लोगों को खुश किया गया है।

बजट देखकर लगा जैसे नरेंद्र मोदी ने जनता को नजरअंदाज कर, सिर्फ 2 मित्रों को साथ लिए कुर्सी बचाने का काम किया है।

कांग्रेस ने जनता को–

* मनरेगा
* फूड सिक्योरिटी एक्ट
* हेल्थ मिशन
* राइट टू हेल्थ
* मिड डे मिल

इन जैसी योजनाएं दी हैं।

लेकिन मोदी सरकार में लोगों से सिर्फ झूठ बोला गया है। इसलिए इस बार नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी की बात नहीं की।

: कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री Mallikarjun Kharge

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी, सरकार से डबल विकास के दावे भ्रामक साबित हुए

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

जयपुर

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तथाकथित डबल इंजन की सरकार से डबल विकास के भ्रामक दावे के बगैर प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण समाप्त नहीं होता था।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है-वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गए बजट में राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है। ऐसा लगा कि राजनीतिक कारणों से केन्द्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया हो।

भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से हमारे राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी परन्तु पूरे बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक नहीं आया जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तथाकथित डबल इंजन की सरकार से डबल विकास के भ्रामक दावे के बगैर प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण समाप्त नहीं होता था।

हमें आशा थी कि केन्द्र सरकार इस बजट में एफ्छढ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देगी एवं एफ्छढ के लिए विशेष फंड मिलेगा लेकिन केन्द्र सरकार ने एफ्छढ पर भी कोई घोषणा ना कर राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। पहले भाजपा सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का था परन्तु अब 5 साल में 1 करोड़ इंटर्नशिप एवं 5,000 रुपये महीने देने की घोषणा बजट में की गई है।

महंगाई को काबू करने के लिए इस बजट में कोई उपाय नहीं किए गए हैं। ना तो पेट्रोल डीजल पर कोई टैक्स कम किया गया और ना ही रसोई गैस सस्ती की गई। राजस्थान में हमारी सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया। जब राजस्थान राज्य ऐसा कर सकता है तो केन्द्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद जनता निराश है। ऐसा दिशाहीन बजट देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शायद ही कामयाब हो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा- ED मुझे गैरकानूनी तरीके से फंसा रही है

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

-

बेंगलूर

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनको 'कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम' घोटाले में फंसाने की साजिश हो रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से फंसाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। सिद्धारमैया ने वाल्मीकि निगम में 187 करोड़ रुपये की अनियमितताओं की जांच के दौरान ईडी की कथित मनमानी के खिलाफ विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगाए।

सिद्दरमैया ने दावा किया कि ईडी ने सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कल्लेश को पूछताछ के लिए बुलाया और उन पर लिखित में यह देने के लिए दबाव डाला कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया, 'ईडी के अधिकारियों ने कल्लेश को मेरा और अन्य मंत्रियों का नाम लेने के लिए मजबूर किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजकोष से 43.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।' उन्होंने कहा, 'हमारा उस घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है। न तो मेरी और न ही वित्त विभाग की उसमें कोई भूमिका है। कल्लेश को धमकाया गया क्योंकि वे (ईडी) गैरकानूनी तरीके से मुझे फंसाना चाहते हैं।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्लेश की शिकायत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया, 'केंद्र राज्य सरकार को अस्थिर करना चाहता है, मुझे निशाना बनाना चाहता है, मेरी छवि खराब करना चाहता है और राज्य के लोगों के बीच यह धारणा बनाना चाहता है कि हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हैं।' सिद्दरमैया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान कई घोटाले हुए लेकिन ईडी जांच में शामिल नहीं हुई।

उन्होंने कहा, 'ईडी और सीबीआई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है। हम इस मुद्दे को कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद में उठाएंगे। लोकतंत्र में यह बेहद खतरनाक कदम है।' सिद्दरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान से बात की है जो फैसला लेगी। उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, मंत्रियों और विधायकों ने प्रदर्शन में भाग लिया।

रीवा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

मध्यप्रदेश के रीवा में दबंगों द्वारा दो महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़कर उनकी हत्या की कोशिश करने की घटना के खिलाफ मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे जी सहित अन्य महिला साथियों ने आज रीवा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह की जघन्य घटना होना, लचार कानून व्यवस्था और बढ़ते महिला अपराध की बानगी है।

मोदी सरकार ने अपने खोखले वादों को प्रदर्शित करने का किया प्रयास: शशि थरूर

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि कई महत्वपूर्ण बातों को इस बजट में अनदेखा कर दिया गया है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, बजट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार ने अपने खोखले वादों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। सरकार ने ऐसा कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो खोखले वादे करने में तनिक भी पीछे नहीं है, लेकिन इससे कुछ खास होने वाला नहीं है। जनता समझदार है, वो सब देखती है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ₹बजट में केंद्र सरकार ने एक या दो नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्रनहीं किया है। इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं किया गया, जो गरीबों के लिए सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी लाने की दिशा में भी बजट में कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है।

उधर, मौजूदा GDP की दर को कैसे बढ़ाना है, इस दिशा में भी सरकार ने बजट के जरिए यह बता दिया कि देश की

जीडीपी कुछ भी रहे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लोगों के व्यक्तिगत आय में कैसे इजाफा हो, इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही है। पिछले दस सालों में लोगों की आय में गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कुछ ऐसा है, जिससे खुश हुआ जा सके।₹

उन्होंने आगे कहा, "Share Market से जुड़े लोगों ने भी बजट को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया ही दी है। मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे लोग खुश हो सकें।

मुझे लगता है कि सरकार को अपने इस बजट को लेकर एक दफा फिर से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो उसे आगामी दिनों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है।₹

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पूर्ण बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न कारकों को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत करने की कोशिश की गई है।

इसके अलावा, कैसे देश में विकास की गति को तेज किया जा सके, इस दिशा में भी बजट के जरिए नई रूपरेखा खींचने का प्रयास किया गया है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे लोगों के कल्याण से जुड़ा बजट बताया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें लोगों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

ध्यान दें, इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) संपन्न होने के बाद पूर्ण बजट पेश किया गया है। इसमें केंद्र सरकार ने समाज के विभिन्न तबकों के लोगों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है।

बाबरपुर जिला कार्यकारिणी बैठक !

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री ऊ५ीह्ली१ ं५ जी की अध्यक्षता में आज बाबरपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक ली गई।

बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई, उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी अपने सुझाव रखे और अध्यक्ष जी ने सभी को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर दिल्ली के जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाने का निर्देश दिया।

इस दौरान श्री अनिल भारद्वाज जी चेयरमैन कम्युनिकेशन दिल्ली कांग्रेस, पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद, श्री भीष्म शर्मा जी, श्री वीर सिंह धीगन जी, पार्षद हाजी ज़रीफ़ जी, श्री जीतेंद्र बघेल जी, पूर्व पार्षद चौधरी अजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष चौधरी ज़ुबैर अहमद जी, पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश जैन जी, श्री राजकुमार जैन जी, आब्जर्वर अशोक जैन जी मौजूद रहे।

10 साल के बाद केंद्र सरकार ने माना कि रोजगार राष्ट्रीय संकट: कांग्रेस

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है तथा केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

पार्टी महासचिव JaiRam Ramesh ने यह भी कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वह इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है जिसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ एक साल तक हर महीने 8500 रुपये देने का वादा किया था। Congress ने इस कार्यक्रम को 'पहली नौकरी पक्की' नाम भी दिया था।

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी।

उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा

रमेश ने '' पर पोस्ट किया, ''वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र-2024 से सीख ली है, जिसमें इसका 'इंटर्नशिप' कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे 'पहली नौकरी पक्की' कहा गया था। हालांकि, अपनी चिरपरिचित शैली में योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य (एक करोड़ इंटर्नशिप) के साथ, सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।''

उन्होंने दावा किया, ''10 साल के इनकार के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अंततः चुपचाप स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।''

रमेश ने कहा कि अब तक बहुत देर हो चुकी है और लगता है कि बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है

बजट को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया गया: बन्ना

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

रांची। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बजट में एक बार फिर मिडिल क्लास परिवार को टैक्स के बोझ से दबा दिया है। चुनाव जीत के बाद लगा था टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन यह उल्टा हो गया और मध्यम वर्ग के ऊपर लगता है चुनावी खर्च थोप दिया है। युवाओं को नौकरी के बदले इंटर्नशिप का झुनझुना थमा दिया गया।

किसानों और महिलाओं की फिर से उपेक्षा की गयी। कामगार और मजदूरों को ठगा गया है। बजट को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया गया है। झारखंड में केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रभारी बने हैं, लेकिन झारखंड की जनता को कुछ नहीं दिला सके। आश्चर्य है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट आइवाश है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विकास फंड देना और झारखंड को उपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक है।

बजट देश की जनता की आशाओं पर वज्रपात, झारखंड के लिए नील बट्टा सन्नाटा: राजेश ठाकुर

संवाददाता ।कांग्रेस दर्पण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश की जनता की आशाओं पर वज्रपात और झारखंड के लिए नील बट्टा सन्नाटा है। बजट का फोकस जनता नहीं, बल्कि सत्ता है और यह इस देश की विडंबना है।

ठाकुर ने मंगलवार को बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट उदाहरण बनकर रह गया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला भाजपा ने केंद्रीय बजट में चुकाया है।

उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि कुल बजट का सिर्फ एक से दो प्रतिशत तक की राशि का प्रावधान पूरे देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है और बातें उत्पादकता बढ़ाने की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस बजट में राजनीतिक सहयोग की कीमत चुकाने की विवशता साफ दिखाई पड़ रही है।

ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन निजी खपत के रिकॉर्ड सुस्ती पर बजट पूरी तरह मौन है। वर्ष 2016 से 2022 के बीच में 24 लाख उत्पादक कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इनके लिए सिर्फ क्रेडिट गारंटी की बात की गई है। ठोस कुछ भी नहीं किया गया है। बजट में जिस Physical Consolidation की बात की गई है उस लक्ष्य 4.5 फीसदी को वढअ की सरकार ने 2014 में ही पा लिया था।

किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि हो सके। इसके विपरीत रिसर्च और कृषि संबंधित क्षेत्र के लिए प्रावधान किया जाना पिछले दरवाजे से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

ठाकुर ने कहा कि इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिले, बल्कि यूं कहें कि आम लोगों को इस बजट से कोई राहत नहीं है। उन्हें बजट के नाम पर झुनझुना भी नहीं दिया गया। वित्त मंत्री की ओर से पेश बजट से स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर होना होगा। सरकारी नियुक्तियां की संभावना को खत्म करने की दिशा में यह बजट पहला कदम है।

जनसंवाद कार्यक्रम

रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रजरप्पा में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आदरणीय श्री गुलाम मीर साहब के संबोधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ।

जन सौहार्द से लबरेज कांग्रेस पार्टी जनहित के कार्यों के लिए सदा अग्रसर है। इस ध्येय का संचार आज के जनसंवाद कार्यक्रम में हुआ।